Date :- 26/5/2020	Degree Part-II (Hons.)
Content Writer :-	Paper :- II
Dr. Abhay Kumar Pathak	Content of Paper :-
Deptt. of Economics,	Indian Economy
Marwari College,	Module :- 2
Darbhanga (LNMU)	

TOPIC :- ECONOMIC PLANNING IN INDIA AND ITS OBJECTIVES

(भारत में आर्थिक नियोजन एवं उसके उद्देश्य)

भारत में आर्थिक नियोजन के अवधारणा पर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित कराने वाले सर एम० विश्वेश्वरैया थे। इन्होंने अपनी पुस्तक "भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था" के द्वारा भारत में नियोजन के विश्लेषण पर अपने विचारों की सार्थकता पर प्रकाश डाला। 1938 में पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की गयी। परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ हो जाने के कारण इस समिति द्वारा आर्थिक नियोजन की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं कर पायी। जनवरी 1944 में मुम्बई के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक योजना प्रस्तुत की जिसको मुम्बई योजना नाम दिया गया। इसके उपरान्त विभिन्न तरह के विचारधाराओं द्वारा भिन्न-भिन्न नामों से योजना को प्रस्तुत किया गया लेकिन ये योजनाएं कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकी।

वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार गठित हो जाने के उपरान्त के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में गठित समिति ने योजना आयोग के गठन का सुझाव दिया। इस सुझाव के आधार पर 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया तथा भारत में आर्थिक नियोजन का विधिवत प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 को किया गया। योजना आयोग का कार्य योजनाएं बनाना, उनको कार्यरूप में परिणत करने का सुझाव देना तथा योजना के प्रगति का मूल्यांकन करना है। अबतक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 6 वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

वर्ष 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI) का गठन किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह संस्थान भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रही है। यह संस्था केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य कर रही है।

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य :-

सन 1951 से आरम्भ की गयी आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया के निम्नांकित मुख्य उद्देश्य हैं :-

(1) आत्मनिर्भरता :-

योजनाओं के प्रारम्भ से ही आत्मनिर्भरता की बात कही गयी है, लेकिन तृतीय योजनाकाल से इस पर विशेष बल दिया गया है। पाँचवीं योजना में तो विदेशी सहायता पर निर्भरता को न्यूनतम करने की बात कही गयी थी। इतना ही नहीं नौवीं योजना से बारहवीं योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता के प्रयासों को मजबूत करना रहा है। आज के इस कोरोना (कोविड-19) महामारी के भीषण दौर में भी भारत सरकार द्वारा स्वदेशी वस्तुओं तथा अन्य आधार पर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रबल एवं सफल प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को आर्थिक नियोजन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

Maharaza

(ii) सवंगीण आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि :- भारतीय नियोजन का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय आय एवं प्रतिव्यक्ति आय में तीव्र गति से वृद्धि करना रहा है जिससे कि जनसाधारण के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके।

(iii) कल्याणकारी राज्य की स्थापना :- भारतीय योजना का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना रहा है जिसके लिए आय एवं संपत्ति की असमानता को दूर करने की बात प्रथम योजना से ही प्रत्येक योजना में की जा रही है। अतः सभी योजनाओं में गरीबी उन्मूलन एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में रहा है।

(iv) रोजगार के अवसरों में वृद्धि :- भारतीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का रहा है। इस उद्देश्य को प्रत्येक योजनाओं में समाहित किया जाता रहा है।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार :- भारत में आर्थिक नियोजन का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे कि जिन क्षेत्रों में निजी उद्योगपति भारी विनियोग के कारण उद्योग स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जा सके ताकि निजी क्षेत्र के

प्रतियोगिता कर उनके शोषण की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(vi) समाजवादी समाज की स्थापना :- भारत के सभी आर्थिक योजनाओं में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए असमानताओं को कम करने तथा आम जनों को सामाजिक न्याय दिलाने का प्रयास किया गया है।

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है यह एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे पूर्ण सफल बताया है तो कुछ ने पूर्ण असफल करार दिया है। हम इसका विश्लेषण कर यह कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन आंशिक रूप से ही सफल रहा है तथा इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।